>

Title: Need to sanction Rs. 6921 Crore to Rajasthan for maintenance of Indira Gandhi canal, as requested by the State Government.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान शून्य काल में आकर्षित करना चाहता हूं। मैं राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र बीकानेर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सैंकिंड फेज (आर.डी. 620 के बाद का क्षेत्र) में जुलाई-2012 तक 10.50 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र खोला जा चुका है। केंद्रीय जल आयोग के मापदंडों के अनुसार इसके रखरखाव के लिए प्रवाह क्षेत्र में 705 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से लगभग 74.3 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की आवश्यकता होती है जबकि इसके विरुद्ध इस वर्ष केवल 17.10 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। नहरों की देखभाल और संचालन का कार्य जमीन स्तर पर करने वाला कार्यभारी संवर्ग डाइंग कैडर है जिसके फलस्वरूप कार्मिकों के पद निरंतर समाप्त हो रहे हैं।

महोदय, आप किसी कमेटी में बीकानेर गए होंगे और आपने रेगिस्तानी एरिया भी देखा होगा। बीकानेर के आसपास श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर जिले आते हैं जहां यह नहर पहुंची है। इस नहर में टेल एण्ड पर जो लोग रहते हैं उन्हें सिंचाई के साथ पीने के पानी की उपलब्धता इसी नहर से होती है। भारत सरकार, केंद्रीय जल आयोग और योजना आयोग को राजस्थान सरकार ने 6921.31 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भेजा है। हम रेगिस्तानी इलाके के लोग हैं इसलिए हमारी मांग है कि हमें यह राशि 90 और 10 रेश्यो के आधार पर दी जाए यानी 90 परसेंट केंद्र सरकार और 10 परसेंट राजस्थान सरकार का होना चाहिए। केंद्र सरकार कह रही है कि हम आपको 50:50 के आधार पर राशि देंगे। इस तरह तो हम काम कर ही नहीं पाएंगे। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, वे राजस्थान से आते हैं। केंद्र सरकार अगर 50:50 की रेश्यो में राशि देगी लेकिन राजस्थान सरकार अपना हिस्सा आवंटित करने की स्थिति में ही नहीं है। हमारा कहना है कि नहरों का इतना बड़ा इफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है। मैंने यूपी और कई और जगह देखा है कि नहरें बनी हुई हैं लेकिन डिसिल्टिंग नहीं हो रही है। पानी नहीं है। एक तरफ तो हम नई नहर नहीं बना सकते हैं और दूसरी तरफ डिसिल्टिंग पूरे देश की समस्या बन गई है। एक तरफ सिंचाई के साधन नहीं बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ ऑलरेडी जो इफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी मरम्मत और नहरों की सफाई के लिए पैसा नहीं है।

मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग है कि राजस्थान सरकार ने 6921.31 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी नहर की सफाई, डिसिल्टिंग, प्रिंकलर सिस्टम, खराब पंपों के लिए 90:10 रेश्यो के आधार पर भारत सरकार को भेजा, उसे तुंत स्वीकृत किया जाए। इसके साथ आईबीपी प्रोजेक्ट में सभी डीडीपी एरिया को सम्मिलित किया जाए।

सभापति महोदय : एलीगेशन में नाम नहीं लेना है।